चावल और गेहूं की मांग, इनके आवंटन और उठान निम्नानुसार हैं:-

जिन्स	मांग	आवंटन	उठान
चावल	1500 टन	1500 टन	नगण्य
गेहूं	17000 टन	12000 टन	6200 टन

जनवरी, 1996 से प्रभावी पंजाब का लेवी चीनी का मासिक कोटा 8619 टन बैठता है जिसे दिसम्बर, 96 जनवरी, 97 और फरवरी, 97 के लिए 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था जैसाकि अन्य राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के आवंटन अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति , केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं । ये आवंटन अनुपूरक होते हैं। पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

पंजाब सहित अधिकाशं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों लेवी चीनी का आवंटन 1.1.96 से 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकडों के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं और ये उनकी मांग के आधार पर नहीं किए जाते हैं।

एफ.सी.आई. की आर्थिक लागत

1545. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक-लागत में विगत वर्षो में निरंतर वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक-लागत की अनुमानित राशि क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1996-97 में आर्थिक-लागत का पूर्वानुमान लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) 1993-94 से 1996-97 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए गेंहू और चावल की इकानमिक लागत निम्नानुसार है:-

(रूपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	इकानामिक गेंहू	लागत चावल
1993-94	532.03	665.10
1994-95	551.17	694.71
1995-96 (संशोधित अनुमान)	563.57	746.72
1996-97 (संभावित)	650.00	811.00

देश में औद्योगिक जिले

1546. **श्री गोपाल सिंह जी . सोलंकी**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त देंश में राज्य-वार विशेषकर गुजरात राज्य में औद्योगिक जिलों की संख्या कितनी-कितनी हो जाएगी;

(ख) उन राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योगो मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) "उद्योगो रहित जिला" योजना' 1983 के तहत, जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) कार्य योजना, 1979-80 के अनुसार देश में कुल 93 जिलों की "उद्योग रहित जिलों" के रूप में पहचान की गई थी । गुजरात में डोंगरा जिले की पहचान ऎसे जिले के रूप में की गई थी जिसे "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व 9 एन आई डी केन्द्रो को भारत सरकार द्वारा जून, 1988 में प्रारंभ की गई नई विकास केन्द्र योजना के तहत विकास केन्द्रों में बदल दिया गया थ ताकि एन आई डी योजना, जो बन्द कर दी गई थी, को बदला जा सके।

(ग) और (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत देश -